

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 29, सोमवार, शाके 1943-सितम्बर 20, 2021 <i>Bhadra 29, Monday, Saka 1943- September 20, 2021</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 02, 2021

संख्या एफ.4(44)/कृषि (गुप-2)/2019 :-राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना - 2019 जिसे की आगे “योजना” कहा गया है, में योजना के पैरा संख्या 14 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए योजना में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

मद संख्या 02 परिभाषा खण्ड में “जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति” के पश्चात् एवं “कृषक” के पूर्व नया प्रावधान “परिवार” की परिभाषा को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है-

“परिवार से तात्पर्य स्वयं, पति या पत्नी एवं आश्रित अव्यस्क बच्चें होगा।”

मद संख्या 02 परिभाषा खण्ड में “कृषक” की परिभाषा के पश्चात् निम्न नया परन्तुक जोड़ा जाता है:-

“परन्तु निम्न श्रेणी के कृषक/व्यक्ति नीति के अन्तर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे-

अ) सभी प्रकार के भूमि धारक संस्थान, एवं

ब) ऐसे कृषक परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हों-

1. पूर्व व वर्तमान संवैधानिक पदधारक,
2. पूर्व व वर्तमान मंत्री /राज्यमंत्री एवं पूर्व/वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/ विधानसभा के सदस्य, पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर, पूर्व व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष,
3. केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों एवं इनसे सम्बन्धित केन्द्रीय या राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं तथा सरकार के अधीन कार्यरत सम्बद्ध कार्यालय/स्वायत्त शासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के सभी नियमित सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी,
4. रू. 10000/- प्रतिमाह से अधिक पेन्शन प्राप्त करने वाले सभी अधिवार्षिकी प्राप्त/ सेवानिवृत्त पेंशनधारी,
5. गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर चुकाने वाले व्यक्ति,
6. डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एवं वास्तुकार जैसे पेशेवर जो कि पेशेवर संस्था में पंजीकृत हो तथा पेशेवराना कार्य कर रहे हों”।

मद संख्या 02 परिभाषा खण्ड में “कृषक उत्पादक संगठन/कंपनी” की परिभाषा के स्थान पर निम्न नयी परिभाषा प्रतिस्थापित की जाती है:-

“कृषक उत्पादक संगठन/कंपनी” से तात्पर्य कृषक उत्पादक संगठनों की सहकारिता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां एवं कंपनी अधिनियम, 1956 (इसमें कोई संशोधन या पुनः अधिनियमित करना सम्मिलित हैं) के भाग ix A में परिभाषित कृषक सदस्यों की ऐसी कंपनी जिसे कंपनी पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (ROC) के द्वारा निगमित किया गया हो, से है। एक कृषक उत्पादक संगठन/ कृषक उत्पादक कम्पनी (FPO/FPC) में इस नीति के तहत लाभ लेने के लिए 50 या अधिक कृषक सदस्य होने चाहिए”

मद संख्या 4(अ) (iii) का प्रतिस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

“अनुदान 3 साल के लॉक-इन-पीरियड्स के साथ क्रेडिट लिंकड बैंक एन्डेड होंगे और भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., रीको, नेब-किसान तथा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा अनुमत अन्य वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों को ही दिया जायेगा।”

योजना में निम्नलिखित नए प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं-

मद संख्या 4(स) के बिन्दु संख्या I. 1. ii) के पश्चात् नया बिन्दु संख्या iii) निम्नानुसार जोड़ा जाता है-

“ iii) सतही मार्ग द्वारा निर्यात

भू-मार्ग से जुड़े सीमावर्ती देशों में निर्यात किये जाने पर सभी प्रकार के भाड़ा अनुदान श्रेणियों में राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देश के समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन की दर से ही आयातक देश की सीमा तक के भाड़े पर परिवहन अनुदान देय होगा।”

मद संख्या 4(स) के बिन्दु संख्या I. 2. i) a. क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं तक सतही परिवहन के पूर्व “/ या आयातक देश की सीमा” जोड़ा जाता है।

मद संख्या 4(स) के बिन्दु संख्या I. 2. ii) a. क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं तक सतही परिवहन के पूर्व “/या आयातक देश की सीमा” जोड़ा जाता है।

मद संख्या 4(स) के बिन्दु संख्या I. 3. i) a. क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं तक सतही परिवहन के पूर्व “/या आयातक देश की सीमा” जोड़ा जाता है।

मद संख्या 4(स) के बिन्दु संख्या I. 3. ii) a. क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं तक सतही परिवहन के पूर्व “/या आयातक देश की सीमा” जोड़ा जाता है।

मद संख्या 4(अ) में दी गई सारणी के बिन्दु संख्या 2 के विशेष विवरण में” प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना/एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना, भारत सरकार द्वारा घोषित मेगाफूड पार्क, कृषि समूह में स्वीकृत परियोजनाएं अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान अनुदान के लिए पात्र होगी।” के स्थान पर निम्न नई शब्दावली प्रतिस्थापित की जाती है-

“राज्य में स्वतंत्र रूप से कहीं भी स्थापित की जाने वाली भारत सरकार की किसी भी योजना में लाभ लेने वाली नीति के अंतर्गत पात्र ऐसी इकाई जिसके लिये योजना के प्रारम्भ के बाद ऋण स्वीकृत किया गया हो एवं अभी

तक व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ हो, 10 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रु. की सीमा में टॉप-अप अनुदान हेतु पात्र होगी।”

परिशिष्ट - iv के जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के गठन की सूची में क्रम संख्या 12 पर सदस्य के रूप में “सहायक महाप्रबंधक/जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड” जोड़ा जाता है।

परिशिष्ट - iv के राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के गठन की सूची में क्रम संख्या 6 से 13 तक सदस्यों के नाम के आगे “या उनके प्रतिनिधि” जोड़ा जाता है।

उक्त अधिसूचना राज्य स्तरीय निगरानी एवं स्वीकृति समिति द्वारा लिये गये निर्णय की संबंधित बैठक दिनांक 10.12.2020 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।